RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 19 JUNE TO 25 JUNE 2024 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 09 ■ अंक 39 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

सच साबित हुई भविष्यवाणी! 5,000 अंक से ज्यादा चढ़ा सेंसेक्स

Page 2

बदल चुके हैं टैक्स से जुड़े ये 8 नियम...

Page 3

इजराइल-गाजा संघर्षः आम जनता के साथ-साथ पर्यावरण को भी चुकानी पड़ रही भारी कीमत

Page 5

editoria!

यूक्रेन शांति सम्मेलन में भारत की स्वतंत्र नीति के क्या हैं मायने?

स्विट्ज़रलैंड में हुआ अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन रूस-यूक्रेन युद्ध जल्द से जल्द समाप्त करने की इच्छा और जरूरत को रेखांकित करते हुए संपन्न हुआ। हालांकि सम्मेलन में शामिल भारत जैसे कई देशों के साझा बयान पर हस्ताक्षर न करने से यह स्पष्ट हो गया कि सम्मेलन की भावना चाहे जितनी भी नेक रही हो, शांति का लक्ष्य हासिल करने में अभी ढेरों व्यावहारिक दिक्कतें हैं। इस सम्मेलन में 90 से ज्यादा देशों का शामिल होना एक पॉजिटिव संकेत कहा जाएगा। इससे यह साफ होता है कि दुनिया का कितना बड़ा हिस्सा यूक्रेन में शांति स्थापित होने की जरूरत को कितनी शिद्दत से महसूस कर रहा है। मगर शांति स्थापित होने की इच्छा जताना एक बात है और शांति स्थापित हो जाना बिल्कुल अलग बात। ध्यान रहे यूक्रेन की पहल पर आयोजित इस शांति सम्मेलन में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था। रूस इसे व्यर्थ की कवायद करार भी दे चुका है। ऐसे में सम्मेलन के साझा बयान में कही गई बातें सांकेतिक महत्व की ही मानी जाएंगी। व्यवहार में इनका कोई मतलब तभी हो सकता है जब युद्ध में शामिल दोनों देश इसे स्वीकार करने पर सहमत हों। भारत ने अपने रुख के जरिए व्यवहार और सिद्धांत के इसी फर्क की ओर संकेत किया है। यह सम्मेलन हो या शांति की दिशा में किया गया इस तरह का कोई भी दूसरा प्रयास, उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे तमाम प्रयासों के पीछे काम कर रहे अलग-अलग विचारों, मतों और दृष्टिकोणों को समझने की कोशिश भी निरंतर जारी रहनी चाहिए। किसी तरह का हल या शांति का कोई फॉर्म्युला इसी प्रक्रिया से निकलेगा। भारत ने स्पष्ट किया कि सम्मेलन में शामिल होने के पीछे उसकी यही सोच थी। सम्मेलन में अपने रुख से भारत ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि वह अपने राष्ट्रीय हितों पर आधारित स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति पर कायम है। गौर करने की बात है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही चीन और भारत के रुख पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रही हैं। चीन स्पष्ट तौर पर रूस के साथ खड़ा दिखता रहा है। लेकिन भारत ने साफ किया कि वह शांति का पक्षधर है। पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति पूतिन को भी साफ-साफ कह चुके हैं कि यह युद्ध का दौर नहीं है। इस बार भी जहां चीन सम्मेलन से दूर रहा, वहीं भारत ने बेहिचक सम्मेलन में शिरकत की, लेकिन स्पष्ट किया कि वह किसी भी एक पक्ष में खड़ा दिखने के बजाय दोनों युद्धरत देशों के बीच बातचीत और सहमति के प्रयासों को ज्यादा तवज्जो देता है।

ओपेक प्लस के उत्पादन में कटौती के बावजूद कच्चे तेल के दाम

100 डॉलर से नीचे रहने की उम्मीद

एजेंसी

रोज़ाना हो रहे उतार चढ़ाव के बावजूद कच्चे तेल के दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जाने के बजाय 90 डॉलर प्रति बैरल के नीचे बने रहने की संभावना है। ये लेख लिखे जाने के वक़्त, अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में लगातार तीन हफ़्तों से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे थे, और ब्रेंट क्रूड ने तो पिछले साल के बाद से अपने सबसे ऊंचे स्तर को छू लिया था (Figure 1). कच्चे तेल के दाम में इस उछाल को अमेरिका में शेल ऑयल के उम्मीद से कम उत्पादन और सऊदी अरब व रूस द्वारा लगातार उत्पादन को सीमित रखने की वजह से पैदा हुई चिंताओं से और बल मिल रहा है। तेल निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) प्लस के सदस्य के तौर पर रूस और सऊदी अरब ने हर दिन तेल के उत्पादन में कटौती को 13 लाख बैरल प्रतिदिन (bpd) को इस साल के आखिर तक जारी रखने का फ़ैसला किया है.अमेरिकी शेल ऑयल का उत्पादन मई 2023 के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुंचने की वजह से बहुत से विश्लेषकों का मानना है कि, कच्चे तेल के दाम में आ रहे उछाल पर लगाम लगने की कोई उम्मीद नहीं है। वहीं दूसरी ओर, ऐसे कई ठोस भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक कारण हैं, जो इस बात की तरफ़ इशारा करते हैं कि कच्चे तेल के दाम में मौजूदा उछाल अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। इसमें चीन में कच्चे तेल की मांग में गिरावट और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में ईरान के दोबारा दाखिल होने जैसे कारण शामिल हैं।

जुलाई में तेल के दाम में गिरावट का अंदाज़ा लगाने वालों का हौसला बढ़ाते हुए चीन द्वारा कच्चे तेल का आयात, पिछले छह महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, वहीं चीन का घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन अपने रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा। चीन की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम रियल एस्टेट सेक्टर के परेशानी में होने की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था इस समय बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति में है। इस वजह से आशंका यही है कि साल 2023 में कच्चे तेल की उसकी मांग सीमित ही रहेगी। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBOC) द्वारा ब्याज दरों में कटौती करना भी चीन की अर्थव्यवस्था में किसी फौरी सुधार की उम्मीद नहीं जगाता है।

कच्चे तेल के दाम में मौजूदा उछाल अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। इसमें चीन में कच्चे तेल की मांग में गिरावट और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में ईरान के दोबारा दाखिल होने जैसे कारण शामिल हैं। तेल के बाज़ार में, हाल के दिनों में अमेरिका के फेडरल रिज़र्व के आक्रामक क़दमों से काफ़ी हलचल मची हुई है। वैसे तो अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को स्थिर बनाए रखा है। लेकिन, उसने ये चेतावनी ज़रूर जारी की है कि इस साल के बाक़ी बचे हुए महीनों में क़र्ज़ लेना महंगा बना रहेगा और 2024 में इसमें उम्मीद से कहीं कम की गिरावट देखी जाएगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा भी ऐसे ही संकेत देने से, फेडरल रिज़र्व की चेतावनी ने बढ़ी हुई ब्याज दरों की वजह से आने वाले कुछ समय तक आर्थिक गतिविधियों और तेल की मांग में कमी आने की आशंकाएं और बढ़ा दीं, जिससे सितंबर महीने में कच्चे तेल के दाम 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद, तेल के बाज़ार में मुनाफ़ाखोरी होती देखी गई।

ऐसे में ये मानना तार्किक लगता है कि तेल के बाज़ार में ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी की वजह से अब इसमें सुधार की उम्मीद की जा सकती है। 18 सितंबर को सऊदी अरब की कंपनी अरामको के सीईओ अमीन नासिर और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुलअज़ीज़ बिन सलमान ने अपने भाषणों में इन कमज़ोरियों की तरफ़ इशारा भी किया था। अरामको के सीईओ ने दुनिया भर में कच्चे तेल की मांग के बारे में कंपनी के दूरगामी नज़रिए में कटौती करते हुए इसे 2030 में 11 करोड़ बैरल प्रतिदिन (bpd) कर दिया। जबकि इससे पहले के अनुमान में कंपनी ने कच्चे तेल की मांग 12.5 करोड़ बैरल प्रतिदिन होने की संभावना जताई थी। वहीं, प्रिंस अब्दुलअज़ीज़ बिन सलमान ने चीन की मांग को लेकर अनिश्चितता, यूरोप में लड़खड़ाते आर्थिक विकास और दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा महंगाई से निपटने के लिए अपनाई गई सख़्त मौद्रिक नीतियों को देखते हुए वैश्विक ऊर्जा बाज़ार में उतार चढ़ाव से निपटने के लिए कड़े नियमन की ज़रूरत जताई।

भारत की बात करें, तो उसके कच्चे तेल के आयात में लगातार तीसरे महीने यानी अगस्त में भी गिरावट देखी गई। इसकी वजह रिफाइनरी के रख-रखाव और मरम्मत का काम और रूस से तेल के आयात में कमी ।आयात में इस गिरावट की वजह सऊदी अरब से तेल के आयात में कमी आना है. रूस और इराक़ के बाद सऊदी अरब, भारत को कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जनवरी 2022 से अगस्त 2023 के बीच भारत का आयात औसतन 75 लाख बैरल प्रतिदिन (bpd) रहा था।

कच्चे तेल की आपूर्ति के पहलू को देखें तो एक्सन मोबिल कॉर्प ने अफ्रीकी देश नाइजीरिया में अपने निवेश को बढ़ावा देते हुए धीरे धीरे वहां से हर दिन लगभग 40 हज़ार बैरल तेल के निर्यात को धीरे धीरे बढ़ाने का वादा किया है। ईरान द्वारा तेल के निर्यात में बढ़ोत्तरी ने भी कच्चे तेल की आपूर्ति में इज़ाफ़ा किया है, जिससे तेल की क़ीमतों में गिरावट आने की संभावना है। दुनिया भर में सरकारों को टैंकर के ज़रिए भेजे जाने वाले तेल के आंकड़े जारी करने वाली कंपनी TankerTrackers.com के मुताबिक़, अगस्त महीने के पहले 20 दिनों में ईरान द्वारा कच्चे तेल का आयात 22 लाख बैरल प्रतिदिन के साथ बढ़कर पांच साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था. ईरान से तेल का ज़्यादातर निर्यात चीन के लिए था।

तेल के दामों में गिरावट की ये संभावना अमेरिका और ईरान के रिश्तों में हुई प्रगति का भी नतीजा है, जिससे ईरान से तेल का निर्यात और बढ़ेगा। ईरान का दावा है कि अमेरिका के साथ क़ैदियों की रिहाई और ज़ब्त संपत्तियां मुक्त करने के समझौते को उसके परमाणु कार्यक्रम समेत अन्य मसलों पर बातचीत आगे बढ़ने का संकेत माना जाना चाहिए।अगर दोनों देशों के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौता होता है, तो अमेरिका और उसके साथी देश ईरान से कच्चे तेल के आयात पर लगे प्रतिबंध हटा सकते हैं, जिससे दुनिया में कच्चे तेल की आपूर्ति और बढ़ जाएगी। सच्चाई तो ये है कि ईरान ने पहले ही अपने यहां कच्चे तेल का उत्पादन 2018 के बाद के सबसे उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है। नाइजीरिया और ईरान भले ही कच्चे तेल के बड़े उत्पादक देश न हों, मगर खुद ओपेक देशों ने अगस्त में 1 लाख 20 हज़ार बैरल प्रतिदिन (bpd) कच्चे तेल के उत्पादन को सितंबर में 2.773 करोड़ बैरल प्रतिदिन पहुंचा दिया था। ओपेक ने फरवरी के बाद पहली बार जाकर सितंबर महीने में तेल का उत्पादन बढ़ाया था।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सरकारी कंपनी BPCL लगाएगी नई रिफाइनरी

50000 करोड़ का करेगी निवेश

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) देश में एक नई रिफाइनरी लगाने की योजना बना रही है। यह रिफाइनरी हर साल 12 करोड़ मीट्रिक टन तेल का उत्पादन करेगी। इकॉनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना पर सरकारी तेल कंपनी लगभग 50,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी अभी तीन राज्यों आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में जगह ढूंढ रही है।

अखबार की रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि, 'भारत को ईंधन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए और रिफाइनरी की जरूरत है, इसलिए BPCL पूर्वी या पश्चिमी तट पर एक और रिफाइनरी लगाने की योजना बना रहा है। अभी बातचीत शुरुआती चरण में है।' उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी नई रिफाइनरी लगाने के लिए उत्तर प्रदेश पर भी विचार कर सकती है। पिछले महीने BPCL के चेयरमैन जी कृष्णकुमार ने बताया था कि कंपनी वित्त वर्ष 2029 तक अपनी रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाकर 45 MMTPA करने की योजना बना रही है। बता दें कि BPCL मुंबई, कोच्चि और Bina (मध्य प्रदेश) में तीन रिफाइनरी चलाती है, जिनकी कुल वार्षिक रिफाइनिंग क्षमता लगभग 36 श्श्ऊईं है।

आगामी पांच सालों में 1.7 ट्रिलियन रुपये का निवेश

ँइण्थ अगले पांच सालों में अपने मुख्य व्यवसायों जैसे ऑइल रिफाइनिंग, फ्यूल मार्केटिंग, पेट्रोकेमिकल और क्लीन एनर्जी में लगभग 1.7 ट्रिलियन रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट के अनुसार, इस कुल पूंजीगत व्यय में से 75,000 करोड़ रुपये रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं के लिए, 8,000 करोड़ रुपये पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए और 20,000 करोड़ रुपये से अधिक इसके मार्केटिंग बिजनेस के लिए आवंटित किए गए हैं।

अखबार की रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि BPCL एक नई रिफाइनरी स्थापित करने पर विचार कर रही है क्योंकि महाराष्ट्र में पश्चिमी तट पर 60 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर बनाने की प्रस्तावित योजना अभी शुरू नहीं हो सकी है। 2015 में, सरकार ने देश की ईंधन और पेट्रो रसायन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 3 ट्रिलियन रुपये की लागत से महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाने का विचार प्रस्तावित किया था।

2017 में, इस परियोजना को अंजाम देने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और सऊदी अरामको के बीच एक ज्वाइंट वेंटर कंपनी – रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स (RRPCL) का गठन किया गया था। सऊदी अरामको की राष्ट्रीय तेल कंपनी की RRPCL में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जबकि तीन भारतीय राष्ट्रीय तेल कंपनियां समान भागीदार थीं। हालांकि, पर्यावरण संबंधी चिंताओं और कई स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण यह परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। वहीं दूसरी ओर, वाहनों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन और नेफ्था की बिक्री बढ़ने के कारण ईंधन की मांग बढ़ रही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 24 में ईंधन की मांग रिकॉर्ड ऊंचाई पर 233.276 मिलियन टन पर पहुंच गई, जो वित्त वर्ष 23 में 223.021 मिलियन टन थी।

भारत रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाएगा

तेल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, भारत अपनी रिफाइनिंग क्षमता में लगभग 80 प्रतिशत का विस्तार करने की योजना बना रहा है। यह क्षमता 2030 तक वर्तमान 252 MMTPA से बढ़ाकर 450 MMTPA तक करने की कोशिश है।

देश छोटी रिफाइनरी लगाने की योजना बना रहा है क्योंकि इनके लिए जमीन अधिग्रहण और सरकारी अनुमतियां मिलना ज्यादा आसान होता है। हालांकि, विश्लेषकों का कहना है कि दुनियाभर में ईंधन की मांग बढ़ रही है, लेकिन नई रिफाइनरी नहीं बन रहीं, बल्कि यूरोप और अमेरिका में मौजूदा रिफाइनरी बंद हो रही हैं। अखबार की रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि, 'दुनियाभर में रिफाइनरी बंद हो रहीं हैं, जिससे तैयार उत्पादों की कमी हो सकती है। ऐसे में भारत इस अवसर का फायदा उठाकर दुनिया के लिए रिफाइनिंग हब बन सकता है। लेकिन इसके लिए हमें रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। आने वाले सालों में ईंधन की मांग मजबूत रहने का अनुमान है।'

ओपेक प्लस के उत्पादन में कटौती के बावजूद कच्चे तेल के दाम

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आगे की संभावना

वैसे तो बहुत से लोगों ने पूर्वानुमान लगाया है कि 2023 के अंत और 2024 के शुरुआती महीनों में कच्चे तेल की क़ीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर रहेंगी. लेकिन इस समय तेल के दाम में जो उछाल आया है वो कई महीनों के दौरान फ़ौरी तौर पर मांग में बढ़ोतरी का नतीजा है. हालांकि ऐसा लगता है कि इस सीमित बाज़ार में तेल के दाम पहले ही अपने शीर्ष तक पहुंच चुके हैं। आगे चलकर ये मांग प्रतिदिन 30 लाख बैरल तक कम हो सकती है। जिसकी वजह से 2023 के आखरि़ी महीनों से लेकर 2024 के शुरुआती दिनों के दौरान कच्चे तेल की क़ीमतों में गिरावट देखी जा सकती है.

भारत की बात करें, तो उसके कच्चे तेल के आयात में लगातार तीसरे महीने यानी अगस्त में भी गिरावट देखी गई. इसकी वजह रिफाइनरी के रख-रखाव और मरम्मत का काम और रूस से तेल के आयात में कमी ।आयात में इस गिरावट की वजह सऊदी अरब से तेल के आयात में कमी आना है। यहां इस बात को समझना ज़रूरी है कि ओपेक प्लस द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन कम करने का फ़ैसला अपने आप में कामयाब रहा है। लेकिन, कुछ भारी भरकम देशों और उनकी दूसरी प्राथमिकताओं को देखते हुए ग़ैर ओपेक उत्पादक देश, अपने उत्पादन को शीर्ष पर पहुंचाकर इस कमी को दूर कर सकते हैं. इसीलिए, कच्चे तेल की क़ीमतों में रोज़ाना उतार चढ़ाव के बावजूद, इसके दाम 100 डॉलर प्रति बैरल जाने के बजाय 90 डॉलर प्रति बैरल के नीचे ही रहने की उम्मीद है।

सच साबित हुई भविष्यवाणी!

5,000 अंक से ज्यादा चढ़ा सेंसेक्स

निवेशकों ने कमाए 42.4 लाख करोड़

नई दिल्ली। एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में हुए आम चुनावों के दौरान कहा था कि चार जून को लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद शेयर बाजार सभी पुराने रेकॉर्ड तोड़ते हुए नए शिखर पर पहुंच जाएगा। हालांकि चार जून को शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली थी और इस पर विपक्षी दल सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन मोदी की चुनाव नतीजों के बाद तेजी की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से बीएसई सेंसेक्स में 5,222 अंक की तेजी आई है। पिछले 9 कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ऑल-टाइम हाई को छुआ है। इससे बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 42.4 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 437.24 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है।

चार जून को निफ्टी में छह फीसदी गिरावट आई थी। लेकिन शेयर मार्केट में उसके बाद आई तेजी ने बाजार के जानकारों को भी चौंका दिया है। कई एनालिस्ट्स ने भविष्यवाणी की थी कि आम चुनावों में खंडित जनादेश के कारण बाजार में 10ड्ड तक की गिरावट आ सकती है। चुनाव नतीजों ने सबको चौंकाया था लेकिन बाजार की तेजी भी कम चौंकाने वाली नहीं है। सैमको सिक्योरिटीज के मार्केट पर्सपेक्टिव्स एंड

रिसर्च के प्रमुख अपूर्व शेठ ने कहा, 'बाजार को यह महसूस हो गया है कि यह गठबंधन सरकार पहले की सरकारों से अलग होगी। पहले के गठबंधनों को कमजोर माना जाता था, क्योंकि उनमें सबसे बड़ी पार्टी साधारण बहुमत के जादुई आंकड़े से काफी दूर रहती थी। इसलिए वह गठबंधन में शामिल दलों पर बहुत अधिक निर्भर रहती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। एनडीए ने पहले ही 10 निर्दलीयों को अपने साथ जोड़ लिया है और अब उसका आंकड़ा 300 के पार हो चुका है।'

एनडीए सरकार का नेतृत्व करते हुए पीएम मोदी ने दिखाया है कि उनकी पार्टी तय एजेंडे के साथ आगे बढ़ेगी। इससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है कि सरकार बाजार अनुकूल नीतियों को आगे बढ़ाएगी। धनवेस्टर की संस्थापक अनुष्का सोहम बटवाल का कहना है कि बाजार का ध्यान अब सरकार की बुनियादी बातों और प्रमुख प्राथमिकताओं पर केंद्रित हो गया है। चुनाव की अनिश्चितता दूर हो गई है और किफायती आवास के लिए पैकेज की मंजूरी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की वापसी से पता चलता है कि सुधार फिर से गति पकड़ेंगे। इसके अलावा, इतिहास बताता है कि गठबंधन सरकारों के कार्यकाल के दौरान बाजारों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। चूंकि देश की बुनियादी स्थिति मजबूत बनी हुई है, इनकम मजबूत बनी रह सकती है। साथ ही नीतिगत पहल और सुधार जारी रह सकते हैं। इसलिए इनसाइडर्स को कोई जोखिम नहीं दिखता है।

लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि चुनाव के बाद बाजार नई ऊंचाई हासिल करेगा। उन्होंने दावा किया कि 4 जून के नतीजों के बाद सेंसेक्स ऐसा झूमेगा कि शेयर मार्केट के प्रोग्रामर भी थक जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी निवेशकों से कहा था कि वे 4 जून से पहले खरीदारी कर लें और बाजार में तेजी आएगी। लेकिन चुनावों के बाद उनके बयान राजनीतिक मुद्दा बन गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शेयर बाजार में 4 जून को आई गिरावट का हवाला देते हुए कहा कि इससे निवेशकों ने 31 लाख करोड़ रुपये गंवा दिए थे। कांग्रेस ने कहा कि तीन जून को मार्केट ऊपर गया और चार जून को गिर गया। पार्टी ने बाजार में आए भारी उतार-चढ़ाव की जांच जेपीसी से कराने की मांग की है।

बदल चुके हैं टैक्स से जुड़े ये 8 नियम...

ITR भरने से पहले जान लीजिए, वरना रुक जाएगा रिफंड

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

वित्त वर्ष 2024 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने का सीजन चल रहा है, जिसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 तय की गई है। इस बीच, टैक्स संबंधी नियमों में कई बदलाव हुए हैं, जो एक टैक्सपेयर्स को जान लेना चाहिए। अगर आप भी ITR भरने जा रहे हैं तो बदले हुए टैक्स नियमों के बारे में जान लेना जरूरी है, वरना आपका टैक्स रिफंड रुक सकता है।

जानकारी के मुताबिक, ऑल इंडिया ITR के डायरेक्टर विकास दहिया का कहना है कि नियमों में बदलाव की अनदेखी करने पर आपके इनकम टैक्स रिफंड पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में भी बताया, जो आपके आईटीआर को प्रभावित कर सकते हैं।

टैक्स स्लैब और रेट में बदलाव

2024 में सरकार ने ऑप्शनल न्यू टैक्स रिजिम के तहत नए टैक्स स्लैब पेश किए हैं, जो बिना किसी छूट और कटौती के कम टैक्स रेट पेश करते हैं। आप ओल्ड टैक्स रिजिम चुनते हैं तो इसमें विभिन्न कटौती और छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। New Tax Regime प्रॉसेस को सरल बनाती है, लेकिन अधिकांश कटौती को समाप्त करती है। कैलकुलेशन के हिसाब से तय कर सकते हैं कि कौन आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है?

पेंशनर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन

पेंशनर्स के लिए 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन शुरू की गई है।यह पेंशन आय पर लागू होती है, जो सैलरी वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध राहत के समान है। पेंशनर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी टैक्स योग्य आय को कम करने के लिए इस कटौती का दावा किया जाए।

धारा 80C और 80D की लिमिट में बदलाव

PPF, NSC और जीवन बीमा प्रीमियम में निवेश करके धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं। हालांकि हेल्थ सेक्टर में डिजिटल भुगतान और बचत को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए गए हैं, जो मेडिकल बीमा के लिए धारा 80ॐ के तहत बढ़ी हुई सीमा में लागू होता है। टैक्सपेयर्स अब अपने परिवार और वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए हाई टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं।

होम लोन के ब्याज पर ज्यादा छूट

पहली बार घर खरीदने वालों के लिए धारा 80EEA के तहत लिए गए होम लोन पर ब्याज के लिए 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती बढ़ा दी गई है। इसका उद्देश्य घर नए होम लोन वाले टैक्सपेयर्स को पर्याप्त राहत देना है।

अपडेट किए गए टीडीएस और टीसीएस

सोर्स पर टैक्स डिडक्शन (TDS) और सोर्स पर टैक्स कलेक्शन (TDS) का दायरा बढ़ाया गया है। नए बदलाव में नॉन-सैलरीड पर्सन और खुद के कारोबार के लिए नई टीडीएस रेट और ई-कॉमर्स लेनदेन के लिए अतिरिक्त अनुपालन आवश्यकताएं शामिल हैं। टैक्सपेयर्स को अपने ऊअए सर्टिफिकेट्स की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके ITR में उचित क्रेडिट का दावा किया गया है।

फेसलेस असेसमेंट और अपील

सरकार ने ह्यूमन इंटरफेस को कम करने और ट्रांसपैरेंसी में सुधार करने के लिए फेसलेस असेसमेंट और अपील मेकनिज्म का विस्तार किया है। टैक्सपेयर्स को प्रॉसेस से परिचित होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नोटिस के जवाब तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन हो जाएं। फॉर्म में बदलाव

ITR फॉर्म में अतिरिक्त खुलासे शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है। खास तौर पर विदेशी संपत्तियों और आय तथा बड़े लेन-देन के संबंध में खुलासा करने के लिए नियम में बदलाव किया गया है। विदेशी निवेश या महत्वपूर्ण वित्तीय गतिविधियों वाले टैक्सपेयर्स को जुर्माने से बचने के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है।

सीनियर सिटीजन के लिए राहत

75 वर्ष या उससे अधिक आयु के सीनियर सिटीजन, जिनकी केवल पेंशन और ब्याज आय है, उन्हें ITR दाखिल करने से छूट दी गई है। बशर्ते बैंक आवश्यक टैक्स काट ले। यह सीधे आय सोर्स वाले सीनियर सिटीजन के लिए अनुपालन बोझ को कम करता है।

मुंबई में अटका मॉनसून अब बढ़ रहा आगे

दिल्ली, यूपी जैसे राज्यों को मिलेगी राहत

एजेंसी

मुंबई पहुंचने के बाद जो मॉनसून ठिठक गया था, वह अब आगे बढ़ने लगा है। इस बीच मौसम विभाग ने भी गुड न्यूज दी है कि मॉनसून जल्दी ही उत्तर भारत की ओर रुख करेगा। इससे कई राज्यों को बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर भारत में दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत का मैदानी इलाका बुरी तरह से तप रहा है। दिल्ली, प्रयागराज, लखनऊ जैसे शहरों में तापमान 48 डिग्री के आसपास मंगलवार को बना हुआ था। बुधवार को सुबह से ही तेज हवाएं चलने से मामूली राहत मिली है, लेकिन अब बारिश को लेकर भी इंतजार खत्म हो सकता है। इसकी वजह यह है कि मुंबई पहुंचने के बाद जो मॉनसून ठिठक गया था, वह अब आगे बढ़ने लगा है। इस बीच मौसम विभाग ने भी गुड न्यूज दी है कि मॉनसून जल्दी ही उत्तर भारत की ओर रुख करेगा।

विभाग ने बुधवार को अनुमान जताया कि 21-22 जून से मॉनसून आगे बढ़ने लगेगा। इससे उत्तर भारत के राज्यों को बड़ी राहत मिलेगी। अनुमान है कि 20 जून से ही पश्चिमी विक्षोभ के चलते मामूली राहत उत्तर भारत के राज्यों को मिलने लगेगी। इसके बाद वीकेंड से राहत में थोड़ा और इजाफा होगा। मौसम विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी सुनील कांबले ने कहा, 'मुंबई पहुंचने के बाद मॉनसून की गतिविधि ठहर गई थी। लेकिन अब इसमें धीरे-धीरे गति आ रही है। यह 21 से 22 जून तक तेजी पकड़ेगा और तटीय महाराष्ट्र में अच्छी खासी बारिश होगी।'

उन्होंने कहा कि मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में कुछ दिनों में हल्की बारिश होगी। बता दें कि बुधवार की सुबह भी मुंबई में हल्की बारिश हुई है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा राहत नहीं मिली है। बता दें कि मॉनसून 9 जून को हुई मुंबई पहुंच गया था। सामान्य शेड्यूल से दो दिन पहले ही मॉनसून मुंबई पहुंचा था। इसके बाद उसने थोड़ी गति पकड़ी और उत्तर महाराष्ट्र एवं विदर्भ को कवर कर लिया। इसके बाद से थोड़ा अटक गया था, लेकिन अब फिर से तेजी आने लगी है। हालांकि इस बीच एक चिंता की बात है कि 1 जून से मॉनसून की शुरुआत होने के बाद से अब तक 20 फीसदी कम बारिश हुई है।

मौसम विभाग का यह अनुमान चिंता भी बढ़ा रहा

खासतौर पर 12 से 18 जून के दौरान बारिश में कमी आई है। मौसम विभाग का भी कहना है कि जून में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। यह मौसम विभाग के पुराने अनुमान से उलट है, जिसमें उसने इस साल मॉनसूनी बारिश सामान्य से अधिक रहने की भविष्यवाणी की थी। बता दें कि भारत में खेती के लिहाज से जून और जुलाई के महीने को खेती के लिहाज से अहम माना जाता है। खरीफ की फसल की बुआई के लिए मॉनसूनी बारिश जरूरी होती है।

बराक, ड्रोन... इजरायल ने हथियार निर्यात में तोड़े सारे रेकॉर्ड

भारत बना टॉप कस्टमर, ईरान किलर की दुनिया दीवानी

तेलअवीव। एजेंसी

इजरायल ने गाजा युद्ध के बीच हथियार निर्यात में नया रेकॉर्ड बनाया है। इजरायल ने साल 2023 में 13.1 अरब डॉलर का हथियार निर्यात किया है। इनमें से आधा निर्यात एशिया को किया गया है और उसमें भारत शीर्ष कस्टमर रहा है। पिछले 5 साल में इजरायली हथियारों का निर्यात दोगुना हो गया है। यही नहीं पिछले 3 साल से इजरायली हथियारों का निर्यात लगातार रेकॉर्ड बना रहा है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह इजरायल का अब तक का सबसे ज्यादा हथियार निर्यात है। इसमें इजरायल का एरो डिफेंस सिस्टम भी शामिल है जिसने ईरानी मिसाइल हमले की बारिश को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। इजरायल ने जिन हथियारों को निर्यात किया है, उसमें 36 फीसदी एयर डिफेंस सिस्टम है। यह साल 2022 में 19 फीसदी था। इजरायल ने इसके अलावा रेडॉर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, ड्रोन और गोला बारूद का निर्यात किया है। इससे पहले इजरायल की चर्चित रक्षा कंपनी आईएआई ने गलती से खुलासा किया था कि भारत उसका सबसे बड़ा ग्राहक है। इजरायल का करीब 48 फीसदी हथियारों का निर्यात एशिया और प्रशांत महासागर के देशों में किया गया है। इसके अलावा 35 फीसदी हथियार निर्यात यूरोप में भी किया गया है।

इजरायल ने भारत को जमकर बेचे हथियार

इजरायली रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा निर्यात उसके लिए केंद्रीय प्राथमिकता बन गया है। इजरायल ने यह आंकड़ा तब जारी किया है जब दुनिया के कई देशों ने गाजा युद्ध का हवाला देते हुए इजरायल के हथियारों का बायकाट करना शुरू कर दिया है। कोलंबिया ने कहा है कि वह इजरायल से हथियारों के निर्यात पर रोक लगा रहा है। मई महीने में फ्रांस की अदालत ने इजरायली कंपनियों को रक्षा प्रदर्शनी में हिस्सा लेने से रोक दिया था। इससे पहले इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने खुलासा किया था कि भारत को उसने सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यात किया है। आईएआई ने बताया कि साल 2023 में करीब 1 अरब डॉलर का हथियार भारत को बेचा गया। भारत को इजरायली कंपनी ने एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई की है। भारत की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इजरायली कंपनी के साथ मिलकर बराक 8 सरफेस टु एयर मिसाइल सिस्टम का निर्माण शुरू किया है। यह पूरा सौदा 77 करोड़ डॉलर का है। भारत ने आईएआई को 95 करोड़ 30 लाख डॉलर का हथियारों का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा ड्रोन, रेडॉर, मिसाइल और इलेक्ट्रिक वारफेयर सिस्टम का सौदा इजरायली कंपनी के साथ किया गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है और अभी रूस से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। इजरायल ने जर्मनी के साथ एरो एयर डिफेंस सिस्टम का सौदा किया है जो करीब 4 अरब डॉलर का है। यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस में गिना जाता है। ईरान के साथ मिसाइल युद्ध में इसने अपनी क्षमता साबित की है।

भारतीय सेना के उत्तरी कमांड ने 4.26 करोड़ की अस्मि गन का दिया ऑर्डर

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय सेना के उत्तरी कमांड ने स्वदेशी 'एश्ष् उल्ह खरीदने के लिए 4.26 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। ये गन नजदीकी लड़ाई के लिए शानदार है। इसके सारे ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं। देश में बनी इस गन ने सैनिकों के बीच भरोसा कायम किया है। भारतीय सेना के उत्तरी कमांड ने स्वदेशी 'एश्ष् उल्ह खरीदने के लिए 4.26 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। ये गन नजदीकी लड़ाई के लिए शानदार है। इसके सारे ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं। देश में बनी इस गन ने सैनिकों के बीच भरोसा कायम किया है। अस्मि मशीन पिस्टल की मैगजीन को पूरा लोड करने पर 33 गोलियां आती हैं। यह पिस्टल एक मिनट में 600 गोलियां दाग सकती है। इसका लोडिंग स्विच दोनों तरफ है. यानी दोनों हाथों से ये पिस्टल चलाना आसान होगा।

यमन के हूती विद्रोहियों के हमले के बाद जहाज लाल सागर में डूबा

एजेंसी

यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से निशाना बनाए जाने के बाद मालवाहक पोत लाल सागर में डूब गया। हूती विद्रोहियों के हमले में पोत के डूबने की यह दूसरी घटना है। अधिकारियों ने बुधवार सुबह यह जानकारी दी। ब्रिटेन की सेना के 'यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर' (यूकेएमटीओ) ने क्षेत्र में नाविकों को सचेत करते हुए बताया कि 'द ट्यूटर' लाल सागर में डूब गया। यूकेएमटीओ ने कहा, '' सैन्य अधिकारियों ने बताया है कि उन्होंने समुद्री मलबा और तेल देखा है। माना जा रहा है कि जहाज डूब गया है।'' हूती विद्रोहियों ने पोत के डूबने के संबंध में फिलहाल कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। पोत 'द ट्यूटर' पर एक सप्ताह पहले लाल सागर में हमला किया गया था। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने सोमवार को बताया था कि इस हमले में '' चालक दल के एक सदस्य की मौत हो गई। चालक दल का यह सदस्य फिलिपींस से था।''

चीनी सेना ने एक और पड़ोसी पर किया गलवान जैसा हमला

फिलीपींस के सैनिकों पर चाकू और भाले से अटैक

बीजिंग। एजेंसी

चीन दुनिया में एक ऐसा देश है, जिसका उसके लगभग सभी पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद चल रहा है। भारत के साथ गलवान घाटी में चीन ने लड़ाई की थी। अब कुछ इसी तरह की हरकत चीन ने अपने पड़ोसी फिलीपींस के साथ की है। समुद्र में चीन और फिलीपींस के सैनिकों के बीच विवादित दक्षिण चीन सागर में लड़ाई देखी गई। फिलीपींस के कमांडर ने कहा कि चीन के सैनिक तलवारों, भालों और चाकुओं के साथ लैस थे, जिनका मुकाबला फिलीपींस के सैनिकों ने सिर्फ हाथों से किया। जनरल रोमियो ब्राउनर ने चीनी जहाजों पर फिलीपीनी नौकाओं को टक्कर मारने और उनमें सवार होकर हथियार उठा ले

जाने का आरोप लगाया है।

जनरल ने कहा कि एक फिलिपिनो सैनिक का जहाज से टक्कर के कारण अंगूठा कट गया। वहीं चीन ने अपने कर्मियों को दोषी ठहराने से इनकार कर दिया है। दोनों पर विवादित टापुओं पर अपने-अपने दावे करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कारण खतरनाक मुठभेड़ देखी गई। यह दोनों के बीच बढ़ता तनाव दिखाता है। यह झड़प तब हुई जब फिलीपीन की नौसेना और तट रक्षक दूसरे थॉमस शोल में तैनात सैनिकों को आपूर्ति पहुंचा रहे थे।

नावों को चीनी सैनिकों ने किया बर्बाद

जनरल ब्राउनर ने कहा कि सैनिकों ने चीनी तट रक्षकों को चाकुओं, भालों और तलवार से लैस देखा। यह पहली बार है जब फिलीपींस के सैनिकों ने क्षेत्र में चीनियों को इस प्रकार के हथियार का इस्तेमाल करते देखा है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। जनरल ने कहा, 'वीडियो में चीनी सैनिकों को हमारे सैनिकों की ओर चाकू दिखाते देखा जा सकता है।' चीनी कर्मियों ने कई बंदूकें जब्त कर लीं और नाव की मोटरों सहित अन्य वस्तुओं को नष्ट कर दिया।

हथियार वापस देने की मांग

वीडियो में देखा जा सकता है कि हवा भरी नावों को चीनी कर्मी पंचर कर रहे हैं। जनरल ने इस घटना को चोरी की तरह बताया। उन्होंने कहा, 'उनके पास हमारे ऑपरेशन को हाईजैक करने और हमारे विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर चल रहे फिलीपीन जहाजों को नष्ट करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।' फिलीपींस के सैन्य प्रमुख ने बुधवार को मांग की है कि चीन जब्त की गई राइफल और उपकरणों को लौटाए और हमले में हुए नुकसान की भरपाई करे।

दिखने लगा आत्मनिर्भर भारत का असर

चीन से आयात में आई कमी लेकिन अभी लंबा सफर है बाकी

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया था। अब धीरे-धीरे इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। इस साल के पहले चार महीनों के दौरान चीन से आयात में कमी आई है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी, फरवरी और मार्च में चीन से आयात में गिरावट आई जबकि अप्रैल में यह सपाट रहा। हालांकि अब भी व्यापार संतुलन पूरी तरह चीन के पक्ष में है। यानी चीन से हम बहुत सारा सामान मंगाते हैं और चीन को उसकी तुलना में बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं। अब भी हमारे कई सेक्टर पूरी तरह चीन से होने वाले आयात पर निर्भर हैं। इनमें रिन्यूएबल एनर्जी और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं।मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में चीन से आयात 8.96 अरब डॉलर रहा जो फरवरी में गिरकर 8.09 अरब डॉलर रह गया। मार्च में इसमें और गिरावट आई और यह 7.75 अरब डॉलर रहा। अप्रैल में यह 7.79 अरब डॉलर रहा। जनवरी-फरवरी के दौरान भारत के आयात में चीन की हिस्सेदारी में भी गिरावट आई जबकि इस दौरान ओवरऑल इम्पोर्ट में तेजी देखने को मिली। जनवरी में भारत का कुल आयात 53.35 अरब डॉलर रहा जिसमें चीन ही हिस्सेदारी 16.79 फीसदी रही। फरवरी में भारत का आयात बढ़कर 60.11 अरब डॉलर पहुंच गया लेकिन इसमें चीन की हिस्सेदारी 13.46 फीसदी रह गई। मार्च में भारत के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी 13.53 फीसदी और अप्रैल में 14.4 फीसदी रही।

चीन के साथ व्यापार घाटा

चीन से भारत टेलिकॉम और स्मार्टफोन पार्ट्स, लैपटॉप और पीसी, प्लास्टिक, आयरन एंड स्टील, केमिकल्स, नॉन-असेंबल्ड सेल, लीथियम-आयन बैटरी, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स शामिल हैं। चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करने के लिए भारत नॉन-एसेंशियल कंज्यूमर और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के आयात में कटौती के लिए काम कर रहा है। अप्रैल में चीन के बाद भारत के इम्पोर्ट में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रूस (9.7 फीसदी) की रही। इसके बाद यूएई (6.14%), अमेरिका (5.9%) और सऊदी अरब (5.9%) का नंबर है। रूस, यूएई और सऊदी अरब से भारत ज्यादातर कच्चा तेल मंगाता है।

इजराइल-गाजा संघर्षः आम जनता के साथ-साथ पर्यावरण को भी चुकानी पड़ रही भारी कीमत

एजेंसी

कहते हैं जंग किसी के लिए फायदेमंद नहीं होती। इसमें शामिल सभी पक्षों को कहीं न कहीं इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा ही कुछ इजराइल-गाजा संघर्ष के मामले में भी देखने को मिला। एक ऐसा संघर्ष जो मानव जाति के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं। यह संघर्ष न केवल अब तक हजारों लोगों की जिंदगियों को निगल चुका है। साथ ही इसकी वजह से बुनियादी ढांचें और अर्थव्यवस्था को भी भारी क्षति हुई है।

गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को जो जानकारी साझा की है, उसके मुताबिक पिछले आठ महीनों में यह संघर्ष गाजा में 37,347 जिंदगियों को लील चुका है। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक गाजा पट्टी पर अब तक 85,372 लोग घायल हो चुके हैं। इतना ही नहीं इस संघर्ष की वजह से अब तक लाखों लोगों को विस्थापन की पीड़ा झेलनी पड़ी है। इजराइल में भी अब तक करीब 1,600 जाने जा चुकी हैं। वहीं घायलों का आंकड़ा 14 हजार के करीब पहुंच चुका है।

हालांकि मानवीय त्रासदी के बीच पर्यावरण और जलवायु को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इस बारे में जारी एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि यह संघर्ष इंसानों के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी बड़ी त्रासदी साबित हुआ है, जिसकी वजह से कार्बन उत्सर्जन काफी बढ़ गया।

इस रिपोर्ट में संघर्ष के पहले 120 दिनों के बारे में जो अनुमान जारी किए हैं उनके मुताबिक इन शुरूआती दिनों के

दौरान संघर्ष की वजह से हुआ उत्सर्जन 26 देशों के वार्षिक उत्सर्जन से भी अधिक रहा। वहीं इजरायल और हमास ने इस दौरान युद्ध को लेकर जो निर्माण किए हैं यदि उनकों भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो यह उत्सर्जन 36 देशों और क्षेत्रों के कुल उत्सर्जन से ज्यादा हो जाता है। बता दें कि जहां इस दौरान हमास ने सुरंग नेटवर्क जैसी संरचनाओं का निर्माण किया, वहीं इजरायल ने भी सुरक्षा के लिए लोहे की दीवार जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण और सुदृढ़ीकरण का काम किया।

रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 के इन शुरूआती 120 दिनों में सीधे तौर पर युद्ध की वजह से औसतन 536,410 टन कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) के बराबर उत्सर्जन हुआ था। जो बढ़कर 652,552 टन तक पहुंच सकता है। गौरतलब है कि इस अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर बमबारी, टोही उड़ानों के साथ-साथ रॉकेटों से किए हमलों और सैन्य गतिविधियां में काफी तेजी देखी गई।

संघर्ष की जलवायु को चुकानी होगी भारी कीमत

अनुमान है कि हमास द्वारा 500 किलोमीटर में बनाए सुरंग नेटवर्क की वजह से औसतन 326,700 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन हुआ था। वहीं इजराइल द्वारा बनाई 65 किलोमीटर और छह मीटर लम्बी दीवार की वजह से औसतन 293,310 टन सीओ2 के बराबर उत्सर्जन हुआ। इस नए विश्लेषण के अनुसार, संघर्ष के शुरूआती 120 दिनों के दौरान गाजा में करीब 200,000 बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा या वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इनमें स्कूल, अस्पताल, अपार्टमेंट, विद्यालय के साथ-साथ जल और सीवेज संयंत्र शामिल थे। इस संघर्ष में गाजा की करीब 66 फीसदी इमारतें नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

अनुमान है कि गाजा और इजराइल में इनके पुनर्निर्माण पर करीब 5,000 करोड़ डॉलर का वित्तीय बोझ पड़ेगा। इन बिल्डिंग्स के दोबारा निर्माण और मरम्मत से होने वाले उत्सर्जन को देखें तो वो छह करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर हो सकता है।

हालांकि हर एक ईमारत के निर्माण से कितना उत्सर्जन होगा यह अलग-अलग हो सकता है, लेकिन एक रूढ़िवादी अनुमान के मुताबिक इनमें से हर ईमारत के पुनर्निर्माण या मरम्मत से औसतन 300 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन होगा।

कुल मिलाकर कहें तो गाजा के पुनर्निर्माण की जो कार्बन लागत चुकानी होगी वो बहुत ज्यादा है। अनुमान है कि गाजा के पुनर्निर्माण से होने वाले कुल उत्सर्जन का यह आंकड़ा 135 से भी ज्यादा देशों के वार्षिक उत्सर्जन से अधिक होगा। गौरतलब है कि ऐसा ही कुछ रूस और यूक्रेन के बीच चलते संघर्ष के मामले में भी देखने को मिला था। एक अध्ययन से पता चला है कि यह युद्ध हजारों किलोमीटर दूर भारत, अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस, स्पेन जैसे देशों में भी जैवविविधता को भारी नुकसान पहुंचा सकता है।इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह के संघर्ष पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डालते हैं, जिनपर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे पहले के अध्ययन भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि सैन्य अभियान वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के करीब साढ़े पांच फीसदी के लिए जिम्मेवार हैं, फिर भी इस उत्सर्जन को अक्सर बहुत कम रिपोर्ट किया जाता है। ऐसे में शोधकर्ताओं ने जलवायु गणनाओं में इस उत्सर्जन को भी ट्रैक और शामिल करने पर जोर दिया है।

इस बारे में अध्ययन और लंदन के क्वीन मैरी विश्वविद्यालय से जुड़े शोधकर्ता डॉक्टर बेंजामिन नेमार्क ने प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से कहा है, 'चूंकि दुनिया जलवायु परिवर्तन और सैन्य संघर्षों के दोहरे संकट से जूझ रही है, ऐसे में युद्ध के पर्यावरणीय प्रभावों को समझना और कम करना बेहद महत्वपूर्ण है।'

अध्ययन से जुड़े अन्य शोधकर्ता पैट्रिक बिगर ने प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से कहा कि, 'खतरे में पड़ा हर जीवन मायने रखता है। हालांकि यह अध्ययन हमें याद दिलाता है कि सशस्त्र संघर्ष हमें भयावह गर्मी के कगार पर धकेल रहे हैं।' रिपोर्ट में संघर्षों के जलवायु पर पड़ते प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें सीमित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के माध्यम से सैन्य उत्सर्जन की तत्काल रिपोर्टिंग की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है।

भारतीय पर्यटकों के लिए तरस रहा मालदीव, संख्या में जबरदस्त गिरावट

मालदीव। एजेंसी

मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त गिरावट आई है। इस कारण मालदीव के होटल, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट जैसे कारोबार को भारी नुकसान पहुंचा है। मालदीव में खर्च करने के मामले में भी भारतीय शीर्ष पर काबिज हैं। भारतीय पर्यटक दूसरे देशों के यात्रियों की तुलना में हर मौसम में मालदीव की यात्रा करते थे। इस बीच आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि जून में भारत से मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या में 2.5 प्रतिशत की स्पष्ट गिरावट आई है। इस गिरावट का कारण दोनों देशों के बीच जारी तनाव और प्रचंड गर्मी को माना जा रहा है।

मालदीव के पर्यटन मंत्रालय ने क्या कहा

मालदीव के पर्यटन मंत्रालय ने खुलासा किय है कि जून में अब तक 44,013 से अधिक पर्यटक आ चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 जून से 12 जून के बीच माले में स्थित वेलाना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (वीआईए) पर कुल 44,013 पर्यटकों का स्वागत किया गया। इस साल के आगमन में पिछले वर्ष के 8,54,405 से 9.6% की वृद्धि और 2022 के 7,47,183 से उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि जून में औसतन हर दिन लगभग 3,668 पर्यटक आ रहे हैं और पर्यटक सात दिनों तक मालदीव में रुक रहे हैं।

इस साल कितने पर्यटक मालदीव पहुंचे

2024 की शुरुआत से मालदीव ने कुल 9,36,258 आगंतुकों का स्वागत किया है। जनवरी के दौरान, देश ने 192,385 आगंतुकों का स्वागत किया, इसके बाद फरवरी में 217,392, मार्च में 194,227, अप्रैल में 168,366 और मई में 119,875 आगंतुकों का स्वागत किया। 2024 के लिए अब तक दैनिक औसत 5,709 है, और पर्यटक औसतन आठ दिनों तक रुक रहे हैं।

चीन के बाद किस देश के पर्यटक सबसे ज्यादा

60,699 आगंतुकों के साथ चीन सबसे आगे है, उसके बाद रूस, इटली और यूके का स्थान है, जो मालदीव के पर्यटन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत, जो पहले पिछले तीन वर्षों से पर्यटकों के आगमन का प्रमुख स्रोत था, 31,437 पर्यटकों के साथ छठे स्थान पर आ गया है। भारत और मालदीव के बीच संबंध, जो पारंपरिक रूप से मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ घनिष्ठ हैं, जनवरी 2024 में मालदीव के कैबिनेट मंत्रियों द्वारा अपमानजनक टिप्पणियों और नस्लवाद पर चिंताओं के बाद तनावपूर्ण हो गए, जो भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ भारत पर लक्षित थे।

जीएसटी परिषद की शनिवार को बैठक, ऑनलाइन गेमिंग कराधान पर चर्चा की संभावना

नयी दिल्ली। एजेंसी

जीएसटी परिषद शनिवार को होने वाली बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श कर सकती है। इनमें ऑनलाइन गेमिंग पर कराधान और संबंधित पक्ष सेवाओं पर कंपनी गारंटी के अलावा दूरसंचार कंपनियों के भुगतान की गई स्पेक्ट्रम फीस पर कर लगाने का मुद्दा भी शामिल है।जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी। इस परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। इस बैठक में माल और सेवा कर (जीएसटी) की दरों को तर्कसंगत बनाने पर गठित मंत्री समूह (जीओएम) की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने पर हुई प्रगति पर भी चर्चा होने की संभावना है। जीएसटी परिषद की यह बैठक आठ महीने के अंतराल के बाद हो रही है। इससे पहले, जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक सात अक्टूबर, 2023 को हुई थी। जीएसटी परिषद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए दांव के पूरे मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के निर्णय की समीक्षा कर सकती है। यह फैसला एक अक्टूबर, 2023 से लागू हुआ है। जीएसटी परिषद ने जुलाई और अगस्त में अपनी बैठकों में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ को कर-योग्य दावों के रूप में शामिल करने के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी दी थी। साथ ही स्पष्ट किया था कि दांव के पूरे मूल्य पर 28 प्रतिशत कर लगेगा। उस समय कहा गया था कि इस फैसले के क्रियान्वयन के छह महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।

फोनपे पेमेंट गेटवे ने रेफ़रल प्रोग्राम की शुरुआत की

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

फोनपे पेमेंट गेटवे ने अपने रेफ़रल प्रोग्राम शुरू करने की सूचना दी है। फोनपे इंड पार्टनर प्रोग्राम उन सभी के लिए बनाया गया है जो किसी बिजनेस को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद करते हैं। रेफ़रल पार्टनर के रूप में, वे अपने क्लाइंट को उनके ग्राहकों से ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार करने के लिए रेफर कर सकते हैं और बिजनेस को बढ़ाने में उनकी मदद कर सकते हैं। यह प्रोग्राम व्यवसायों को इंडस्ट्री में सबसे बेहतर कमीशन दरें प्रदान करता है, जो हर एक लेनदेन पर लागू होती हैं, जिससे उनकी रेफ़रल से होने वाली कमाई काफी बढ़ सकती है। व्यवसाय अपने मर्चेंट को पेमेंट की बेहतरीन सुविधा प्रदान करने के लिए फोनपे इंड पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। यह पार्टनरशिप विश्वसनीयता को बढ़ाती है और ग्राहकों के लिए वे वेंडर पसंदीदा बन जाते हैं, जिससे भरोसा पैदा होता है और बिजनेस में बढ़ोतरी होती है। यह प्रोग्राम डेवलपर और डिजिटल एजेंसियों से लेकर ईं, ऐंश और ऐंए कंपनियों जैसे टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म सहित कई बिजनेस के लिए खुला है। पार्टनर बनने पर हर महीने तय समय पर पेमेंट का लाभ, साथ ही फोनपे इंड के आयोजित कार्यक्रमों के लिए खास आमंत्रण और किसी भी समस्या में मदद के लिए अकाउंट मैनजेर की सुविधा भी मिलती है। टेक्नॉलजी पार्टनर को अतिरिक्त सपोर्ट मिलता है जिसमें उनके प्रोडक्ट को भी साथ चलाने के लिए टेक्नीकल सहायता शामिल है।

खाना खाने के बाद उसी थाली में हाथ धोने से जीवन में आ सकती है कंगाली, जानें वास्तु शास्त्र के भोजन के नियम

आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा, जो खाना खाने के बाद उसी थाली में हाथ धो देते हैं। ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह आलस्य को माना जाता है लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लग जाता है। वहीं, धीरे-धीरे आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहां आपके पैसे ज्यादा खर्च होने लगते हैं। व्यर्थ की चीजों पर धन खर्च करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। आइए, जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार भोजन के नियमों से जुड़ीं खास बातें।

डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
इंदौर (म.प्र.)

माता अन्नापूर्णा हो जाती हैं नाराज

वास्तु शास्त्र नियम के अनुसार खाना खाने के बाद उसी थाली में हाथ धोने से माता अन्नापूर्णा नाराज हो जाती हैं। इससे आपको खाना खाने के बाद कुछ रोगों का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं, आपकी इस आदत की वजह से माता लक्ष्मी भी आपके घर में निवास नहीं करती। इस कारण से कभी भी खाना खाने के बाद उसी थाली में हाथ न धोएं।

बिस्तर पर बैठकर न खाएं खाना

ज्यादातर लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाना पसंद करते हैं। आप भी अगर ऐसे ही लोगों में शामिल हैं, तो अपनी इस आदत को आज से ही बदल लें क्योंकि वास्तु शस्त्र के नियम के अनुसार जिस बिस्तर पर सोते हैं, उस पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का जीवन में वास होता है। आप कई रोगों का शिकार हो सकते हैं। साथ ही इससे आर्थिक मंदी का सामना भी करना पड़ सकता है।

एक साथ न परोसें तीन रोटियां

वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार थाली में कभी भी एक साथ तीन रोटियां न परोसें। ऐसा करना भी भोजन के नियमों के अनुसार सही नहीं माना जाता है। आपको अगर एक साथ थाली में कई चीजें परोसने की आदत है, तो आपको दो रोटी परोसनी चाहिए। वहीं, रोटियों को चावल के ऊपर रखें। इससे माता अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती है।

थाली को अच्छी तरह साफ करके ही परोसें खाना

थाली में खाना परोसते समय आपको ध्यान देना चाहिए कि थाली में पानी की बूंदें न हो। ऐसा करने से आपके जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए आपको थाली में खाना परोसते समय थाली को अच्छी तरह कपड़े से साफ करके ही इसमें खाना परोसना चाहिए।

थाली में न छोड़ें खाना

कई लोगों की यह आदत भी होती है कि उन्हें जितना खाना खाना होता है, वे खा लेते हैं लेकिन इसके बाद थाली में खाना छोड़ देते हैं। इस खाने की थाली वे किचन सिंक में भी रख देते हैं। जिस पर बार-बार पानी गिरता रहता है और खाने का अपमान होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस आदत की वजह से आप कई रोगों का शिकार हो सकते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं। भोजन के नियम के अनुसार थाली में जूठा खाना बच जाए, तो इसे अलग कटोरी में निकालकर पशु-पक्षियों के लिए रख दें।

आषाढ़ मास कब से लग रहा है, जानें आषाढ़ में क्या करें क्या न करें

पं. श्री रमेशचंद व्यास
(चैनपुरा वाले)
ज्योतिषयाचार्य एवं रत्न विशेषज्ञ
मो. 9826345104

हिंदू पंचांग का चौथा महीना आषाढ़ 22 जून दिन शनिवार से प्रारंभ होने जा रहा है। इस मास का नाम पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के ऊपर रखा गया है इसलिए इस महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा इन्हीं दो नक्षत्र में रहते हैं। आषाढ़ महीने में कई महत्वपूर्ण त्योहार और व्रत आते हैं और यह माह ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। आषाढ़ मास में देवी दुर्गा, भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान सूर्यदेव की पूजा का विधान है। विधि विधान के साथ देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामना पूरी होती हैं। आइए जानते हैं हिंदू कैलेंडर के चौथे महीने आषाढ़ में क्या करें क्या ना करें...

आषाढ़ मास में क्या करें

आषाढ़ मास में हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी पूजा करें और मंत्र व जप का ध्यान करें।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ रामदूताय नमः, ॐ क्रीं कृष्णाय नमः और ॐ रां रामाय नमः मंत्रों का जप करें।

हर रोज सूर्यदेव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

आषाढ़ मास में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी, भगवान शिव माता पार्वती, सूर्यदेव की पूजा करने का विधान है।

आषाढ़ मास में में दान, यज्ञ, व्रत, देव पूजा, पितृ पूजा करने से भाग्य का साथ मिलता है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है।

गरीब व जरूरतमंद लोगों की मदद करें और धन, कपड़ा, छाता, जल, अनाज आदि का दान करना चाहिए।

आषाढ़ मास में तीर्थयात्रा करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है।

22 जून से आषाढ़ मास प्रारंभ हो रहा है और 21 जुलाई को समाप्त हो रहा है, इसके बाद सावन मास का प्रारंभ हो जाएगा।

आषाढ़ मास में देवशयनी एकादशी, चातुर्मास प्रारंभ, गुप्त नवरात्र प्रारंभ, गुरु पूर्णिमा आदि कई प्रमुख व्रत त्योहार मनाए जाते हैं।

आषाढ़ मास में क्या ना करें

आषाढ़ मास में बैंगन, मसूर दाल, गोभी, लहसुन, प्याज आदि का सेवन करने से बचना चाहिए।

इस मास में मांस-मछली, मदिरा, अन्य नशीले पदार्थ और अनैतिक कृत्यों से दूर रहना चाहिए।

आषाढ़ मास में पत्तेदार सब्जी, हरी सब्जियां बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और तेल वाली चीजों से बचना चाहिए।

इस मास में क्रोध, अहंकार, घमंड आदि चीजों से दूर रहें।

इस मास में किसी को अपमान ना करें और अपशब्द ना बोलें। साथ ही घर पर आए किसी व्यक्ति खाली हाथ ना लौटाएं।

शनि वक्री किस डेट में हो रहे हैं, इस दिन क्या करें, क्या न करें?

पंडित कपिल पाराशर
बनारस वाले ज्योतिष आचार्य वास्तु विशेषज्ञ
6261493070

ज्योतिष में शनि देव को क्रूर ग्रह कहा जाता है. क्योंकि शनि देव बुरे कर्मों का दंड देते हैं. शास्त्रों में शनि देव की पूजा के कई नियम भी बताए गए हैं. वहीं शनि देव की दृष्टि जिसपर पड़ जाती है, उसका बुरा समय शुरू हो जाता है. इसलिए अधिकतर लोग शनि महाराज से भय भी रखते हैं.

शनि वक्री 2024 डेट

एक निश्चित अवधि पर सभी ग्रह मार्गी होते हैं या वक्री होते हैं (सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर). ग्रहों के वक्री होने का अर्थ होता है उल्टी दिशा में गति करना या उल्टी चाल चलना. शनि देव 29 जून 2024 को रात 11 बजकर 40 मिनट को कुंभ राशि में वक्री होंगे और लगभग साढ़े चार महीने तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे. इसके बाद शनि 15 नवंबर 2024 को मार्गी होंगे. आम धारणा है कि, शनि देव की वक्री अवस्था खरतनाक होती है, क्योंकि ज्योतिष में शनि का वक्री होना शुभ नहीं माना जाता है.

शनि वक्री का प्रभाव

विभिन्न लग्न के लिए शनि वक्री का फल भी अलग-अलग होता है. यह जरूरी नहीं की शनि का वक्री होना सभी के लिए अशुभ हो. यदि आपकी लग्न कुंडली में शनि शुभ स्थान पर हों तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. हालांकि शनि वक्री होकर उन राशियों को अधिक दंड देते हैं या परेशान करते हैं, जिनपर शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही हो. लेकिन शनि वक्री के दौरान आप आसान उपायों को कर दुष्प्रभावों से भी बच सकते हैं. आइये जानते हैं शनि वक्री के दौरान क्या करें और क्या नहीं करें.

शनि वक्री के दौरान भूलकर भी न करें ये काम

शनि देव न्यायप्रिय देवता हैं. ऐसे में जब शनि देव वक्री अवस्था में हों तब लोभ, लालच और अधिक महत्वकांक्षाओं से दूर रहें. गरीब, असहाय, मजदूर या बड़े-बुजुर्गों का अपमान न करें और ना ही किसी प्रकार से इन्हें सताएं.

शनि वक्री के दौरान वाणी पर नियंत्रण रखें और वाद-विवाद से दूर रहें. कटुवचन बोलने वालों को शनि देव दंड देते हैं.

शनि वक्री की अवधि में पशु-पशु, साधु-संत, माता-पिता आदि की सेवा करें और भूलकर भी इनका अपमान न करें.

शनि वक्री हो तो करें ये काम

शनि वक्री के दौरान उन लोगों को नदी स्नान करना चाहिए और छाता का दान करना चाहिए, जिनकी कुंडली में शनि शत्रु भाव में बैठे हों या फिर शनि की शुभ दृष्टि न हो.

लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपनी छवि देखें और फिर इस तेल को कटोरे सहित दान कर दें. या पीपल के नीचे रख दें.

शनि वक्री की अवस्था में लोहा, सरसों तेल, काली उड़द, काली तिल, काले वस्त्र, कंबल आदि का दान करना शुभ होता है.

इस अवधि में आप सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करा सकते हैं.

नया घर, दुकान खरीदने जा रहे हैं तो वास्तु से जुड़ी बातें जरुर जान लें, सदा रहेगी लक्ष्मी जी की कृपा

पं. राजेश वैष्णव
शनि उपासक ज्योतिष रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
98272 88490

वास्तु शास्त्र का इस्तेमाल घर, दुकान या व्यापार में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए किया जाता है. वास्तु के अनुसार बनी ये चीजें सुख-समृद्धि लाती हैं और लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है.

अगर आप नया घर या दुकान खरीदने जा रहे हैं तो आपको वास्तु के नियमों का खास पालन करना चाहिए. आइए जानते हैं वास्तु से जुड़ी इन खास बातों के बारे में.

घर और दुकान से जुड़े वास्तु के नियम

वास्तु शास्त्र में दिशाओं का खास ध्यान रखा जाता है. घर या दुकान का मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए. घर में पूजा स्थल ईशान कोण में होना चाहिए जबकि बेडरूम दक्षिण-पश्चिम दिशा में होना चाहिए. वहीं किचन अग्नि कोण यानी दक्षिण-पूर्व दिशा में होना चाहिए.

घर या दुकान का आकार वर्गाकार या आयताकार होना चाहिए. अनियमित आकार वाले भवन वास्तु के अनुसार अशुभ माने जाते हैं.

वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि घर या दुकान में पर्याप्त खिड़कियां होनी चाहिए, ताकि प्राकृतिक प्रकाश और हवा का प्रवेश हो सके. खिड़कियां दक्षिण और पश्चिम दिशा में होनी चाहिए.

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार बड़ा और भव्य होना चाहिए. मुख्य द्वार के सामने कोई बाधा नहीं होनी चाहिए. वहीं घर या दुकान की छत समतल होनी चाहिए.

छत पर ढलान दक्षिण-पश्चिम दिशा से पूर्वोत्तर दिशा की ओर होना चाहिए.

वास्तु के अनुसार, घर या दुकान के लिए हल्के और सफेद रंग का प्रयोग करना चाहिए. इन रंगों से सकारात्मकता का प्रवाह होता है, जो व्यवसाय में तरक्की प्रदान करने में सहायक माने जाते हैं. गहरे रंगों का प्रयोग कम मात्रा में करें.

घर या दुकान में पानी का भंडारण उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए. घर या दुकान में जल निकासी की व्यवस्था उचित होनी चाहिए.

घर या दुकान के आसपास तुलसी, मनी प्लांट, और एलोवेरा जैसे शुभ पौधे लगाएं. कांटेदार पौधों को घर या दुकान के आसपास नहीं लगाना चाहिए.

व्यवसाय को कामयाब बनाने के लिए आप अपनी दुकान में श्रीयंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, क्रिस्टल वाला कछुआ या क्रिस्टल बॉल रख सकते हैं. इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है.

आम जनता पर पड़ रही महंगाई की मार, प्याज-आलू के बाद चढ़ गया टमाटर का भाव

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में आम जनता को महंगाई से कोई राहत नहीं मिली है। जहां एक तरफ भीषम गर्मी से लोग परेशान है तो अब महंगाई ने भी आम जनता को परेशान कर दिया है। एक बार फिर से हरी सब्जियों के साथ टमाटर के दाम में इजाफा हो रहा है। पिछले हफ्ते प्याज और आलू के दाम में बढ़ोतरी हुई थी और अब टमाटर महंगा हो गया है।

हीटवेव और भीषण गर्मी ने आम जनता को डबल झटका दिया है। इस गर्मी के सीजन में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। देश के कई इलाकों में प्याज और आलू के साथ टमाटर भी महंगा होते जा रहा है। पिछले दो हफ्तों में टमाटर के दाम में दोगुना इजाफा हुआ है। शुरुआती समय में टमाटर की कीमत महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में देखी गई थी, लेकिन अब पूरे देश में इसके दाम बढ़ गए हैं। कहा जा रहा है कि टमाटर के दाम और चढ़ सकते हैं।

क्या है टमाटर के भाव

एगमार्कनेट जो कि सरकारी पोर्टल है उसके अनुसार साउथ इंडिया में टमाटर की औसत थोक कीमत 35 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम है। वहीं, कर्नाटक के कुछ बाजारों में टमाटर के दाम 60 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। अगर खुदरा भाव की बात करें तो कई जगह पर टमाटर 80 रुपये प्रति किलो के भाव से मिल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले दो-तीन सप्ताह में टमाटर के दाम एक साल की तुलना में दोगुनी हो गई है। हालांकि, अभी उत्तर-भारत में टमाटर की कीमतों में इतनी तेजी देखने को नहीं मिली है। लेकिन, माना जा रहा है कि जुलाई में सह स्थिति जटिल हो सकती है। दरअसल, जब-जब सप्लाई में कमी आती है तो कीमतों में उछाल आता है।

क्यों महंगा हो रहा है टमाटर

जानकारों के अनुसार इस साल टमाटर के प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हुआ है। भीषण गर्मी की वजह से फूल और फल खराब हो गए जिसकी वजह से उत्पादन भी कम हुआ। इसके अलवा माना जा रहा है कि मंडी में टमाटर का सप्लाई भी ज्यादा नहीं हो रहा है। पिछले एक साल से जुलाई और अक्टूबर के बीच टमाटर के दाम आसमान छूते हैं। कई क्षेत्र में बरसात के मौसम में टमाटर को उगाया जाता है,लेकिन ज्यादा बारिश की वजह से भी कई बार फसल खराब हो जाती है।

कितना महंगा हुआ प्याज-आलू

अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार से एक साल की तुलना में आलू के दाम 43.82 फीसदी बढ़ गए हैं। वहीं, प्याज की कीमत में भी 55.05 फीसदी का इजाफा हुआ है। पिछले साल प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने प्याज के निर्यात को बंद कर दिया था, लेकिन इस चालू कारोबारी साल में फिर से प्याज का निर्यात शुरू हो गया है। टमाटर की कीमतों में करीब 37.29 फीसदी का इजाफा हुआ है। कुछ दिन पहले आई क्रिसिल (ीग्गत) की रिपोर्ट के अनुसार प्याज की कीमतों में 43 फीसदी , टमाटर की कीमतों में 39 फीसदी और आलू में 41 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। भीषण गर्मी और कम बारिश की वजह से सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी की वजह से महंगाई दर ऊंची बनी रहेगी। इक्रा (घ्ीं) का अनुमान है कि जून 2024 में थोक महंगाई 3 फीसदी तक पहुंच सकती है। महंगाई दर को कंट्रोल करने में मानसून की महत्वपूर्ण भूमिका है।

भारत में दलाई लामा से मिलेंगे अमेरिकी सांसद, खबर सुन भड़का चीन

नई दिल्ली। एजेंसी

अमेरिका के सांसद धर्मशाला के दो दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान वह बुधवार को दलाई लामा से मुलाकात करेंगे। चीन ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को तिब्बत पॉलिसी बिल साइन ना करने के साथ और नसीहतें दी है। अमेरिका के सांसदों का एक समूह दो दिनों के धर्मशाला दौरे के लिए भारत में है। इस दौरान अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य तिब्बत के आध्यामिक गुरु दलाई लामा से मुलाकात करेंगे। लगभग 2 साल पहले ताइवान का दौरा करके सुर्खियों में आई अमेरिकी कांग्रेस की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी इस समूह का हिस्सा हैं। यह दल यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष माइकल मैककॉल के नेतृत्व में धर्मशाला का दौरा कर रहा है। मैककॉल और पेलोसी के अलावा, प्रतिनिधिमंडल में अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य, मैरिएनेट मिलर, ग्रेगरी मीक्स, निकोल मैलियोटैकिस, जिम मैकगवर्न और एमी बेरा शामिल हैं। पेलोसी ने अगस्त 2022 में ताइवान का दौरा किया था और चीन ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की वहां यात्रा की तीखी आलोचना की थी।

धर्मशाला के गग्गल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद, मैककॉल ने इस दौरे के बारे में बताया, 'हम हिज होलीनेस दलाई लामा से मिलने और कई चीजों के बारे में बात करने के लिए उत्साहित हैं। इसमें कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक भी शामिल है, जिसमें मूल रूप से कहा गया है कि अमेरिका तिब्बत के लोगों के साथ खड़ा है।' मैककॉल ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन इस विधेयक पर हस्ताक्षर जरूर करेंगे। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (र्एडी) के उच्च-स्तरीय अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। धर्मशाला तिब्बत की निर्वासित सरकार की सत्ता का केंद्र है, जब से दलाई लामा छह दशक पहले भारत में आए थे।

किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं: चीन

इस बीच चीन को यह दौरा नगावार गुज़र रहा है। बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बाइडेन से अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों द्वारा पारित हो चुके बायपार्टीशन तिब्बत पॉलिसी बिल पर हस्ताक्षर न करने के लिए कहा है। वाशिंगटन में मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, विधेयक को कानून बनाने के लिए बाइडेन के हस्ताक्षर का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पिछले बुधवार को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने तिब्बत-चीन विवाद के लिए इस बिल को मंजूरी दी थी। इस बिल को सीनेट से पहले से पास करा लिया गया था। साथ ही यह विधेयक तिब्बत के इतिहास, लोगों और संस्थानों के बारे में बीजिंग द्वारा फैलाई जा रही 'भ्रामक सूचना' का मुकाबला करने के लिए धनराशि मुहैया कराएगा। इस विधेयक का

उद्देश्य तिब्बत पर अपने नियंत्रण के बारे में चीन के बयान का मुकाबला करना और चीनी सरकार और दलाई लामा के बीच संवाद को बढ़ावा देना है।

नई दिल्ली में चीनी दूतावास ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने अमेरिकी पक्ष से 'शिजांग को चीन का हिस्सा मानने और 'शिजांग की स्वतंत्रता' का समर्थन न करने की अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने' का अपील की है। चीन आधिकारिक तौर पर तिब्बत को शिजांग के नाम से संबोधित करता है।

चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने ट्वीट किया, 'चीन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की दृढ़ता से रक्षा करने के लिए दृढ़ कदम उठाएगा।' प्रवक्ता ने कहा, 'यह सभी जानते हैं कि 14वें दलाई लामा कोई विशुद्ध धार्मिक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि धर्म की आड़ में चीन विरोधी अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त एक राजनीतिक निर्वासित व्यक्ति हैं। हम अमेरिकी पक्ष से दलाई समूह की चीन विरोधी अलगाववादी प्रकृति को पहचानने, शिजांग से संबंधित मुद्दों पर चीन से की गई अमेरिका की प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने और दुनिया को गलत संकेत भेजना बंद करने का आग्रह करते हैं।'

चीनी दूतावास ने कहा, 'शिजांग हमेशा चीन का हिस्सा रहा है। शिज़ांग के मामले पूरी तरह से चीन के घरेलू मामले हैं और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की कभी अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति और किसी भी ताकत को कभी भी शिजांग की शांति को भंग करने और चीन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसे प्रयास कभी सफल नहीं होंगे।' इस ट्वीट में उन्होंने नैंसी पेलोसी को टैग भी किया।

रुपया एक पैसे फिसलकर 83.44 प्रति डॉलर पर बंद

मुंबई। एजेंसी

अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया बुधवार को एक पैसे की मामूली गिरावट के साथ 83.44 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच सत्र के अंत में अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपये का आरंभिक लाभ जाता रहा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि डॉलर की मजबूती तथा विदेशों में कच्चे तेल की कीमतों के ऊंचे स्तर पर होने के कारण रुपये में तेजी पर विराम लगा।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 83.39 प्रति डॉलर पर मजबूत खुला और कारोबार के दौरान 83.34-83.48 प्रति डॉलर के दायरे में रहने के बाद कारोबार के अंत में एक पैसे की गिरावट के साथ 83.44 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। मंगलवार को रुपया 12 पैसे की तेजी के साथ 83.43 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ शोध विश्लेषक दिलीप परमार ने कहा, ''कमजोर क्षेत्रीय मुद्राओं और आयातकों की डॉलर मांग ने रुपये को उच्च शुरुआत के बाद नीचे खींच लिया। घरेलू बाजारों में कारोबार अपेक्षाकृत अधिक रहा, जबकि अमेरिकी अवकाश के कारण विदेशी मोर्चे पर कारोबार कम रहा।'' इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी मुद्रा का आकलन करने वाला डॉलर सूचकांक 0.08 प्रतिशत टूटकर 105.17 पर रहा।

अंतराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.40 प्रतिशत बढ़कर 85.67 डॉलर प्रति बैरल पर रहा। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 36.45 अंक की बढ़त के साथ 77,337.59 अंक के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 41.90 अंक की हल्की गिरावट के साथ 23,516.00 अंक पर रहा। कारोबार के दौरान दोनों सूचकांक नये शिखर पर पहुंचे। विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) भारतीय पूंजी बाजार में शुद्ध लिवाल रहे और उन्होंने बुधवार को 7,908.36 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

अर्थशास्त्रियों ने दी सरकार को सलाह, कहा- बजट में इन क्षेत्रों पर करें फोकस

नई दिल्ली। एजेंसी

अगले महीने देश का केंद्रीय बजट 2024 पेश हो सकता है। ऐसे में अर्थशास्त्रियों ने बजट 2024-25 में सरकार को रोजगार सृजन और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने पर फोकस करने की सलाह दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक में भाग लेने वाले अर्थशास्त्रियों ने यह बात कही। भाषा की खबर के मुताबिक, बैठक में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह-संयोजक अश्विनी महाजन, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान (आईएसआईडी) के निदेशक और मुख्य कार्यकारी नागेश कुमार और टीसीए अनंत सहित अन्य लोग शामिल हुए।

उपभोग मांग कोई समस्या नहीं बनने जा रही- खबर के मुताबिक, महाजन ने कहा कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और सरकार को रोजगार पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में तेजी को देखते हुए उपभोग मांग कोई समस्या नहीं बनने जा रही है। नागेश ने कहा कि हमने विनिर्माण क्षेत्र को आगे बढ़ाने की जरूरत पर काफी चर्चा की। उन्होंने कहा कि बजट में एमएसएमई और कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। नागेश ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का दायरा बढ़ाने की वकालत की।

वित्त मंत्रालय ने किया ये पोस्ट- वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा है, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में आगामी आम बजट 2024-25 के संबंध में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बजट-पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इसमें कहा गया कि बजटपूर्व परामर्श बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों, राजस्व, वित्तीय सेवाओं और कॉरपोरेट मामलों के विभागों के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) भी शामिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई के आखिरी सप्ताह में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर सकती हैं।

दुनिया के लिए रहस्य बना शीशे जैसा चमकने वाला मोनोलिथ, अब लास वेगास में आया नजर

न्यूयॉर्क। एजेंसी

अमेरिका के लास वेगास के पास एक रहस्यमयी मोनोलिथ फिर से दिखाई दिया है। इसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान हैं। उन्हें भी नहीं पता कि यह मोनोलिथ यहां कहां से आया है। खोज और बचाव दलों ने नेवादा में एक लोकप्रिय हाइकिंग ट्रेल के साथ इस शीशे से बने स्तंभ की खोज की है। इसे चार साल पहले कोविड-19 महामारी के दौरान पहली बार देखा गया था। इसे गॉस पीक के ऊपर चट्टानों के बीच देखा गया है। अपने शीशे और परावर्तक रूप के कारण यह मोनोलिथ चट्टानी परिवेश में लगभग पूरी तरह अदृश्य हो गया है।

लास वेगास ने क्या कहा

लास वेगास मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग (LVMPD) ने इस मोनोलिथ के बारे में जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। पुलिस ने कहा, 'जब लोग हाइकिंग पर जाते हैं तो हम कई अजीबोगरीब चीजें देखते हैं जैसे मौसम के लिए तैयार न होना, पर्याप्त पानी न लाना... लेकिन इसे देखिए! वीकेंड में, लास वेगास मेट्रो सर्च एंड रेस्क्यू ने घाटी के उत्तर में गॉस पीक के पास इस रहस्यमयी मोनोलिथ को देखा। यह वहां कैसे पहुंचा??'

खंभे के लास वेगास पहुंचने की जानकारी नहीं

इस बात का कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि यह विचित्र खंभा लास वेगास में कैसे पहुंचा। दिसंबर 2020 में पार्टी हॉटस्पॉट में फ्रेमोंट स्ट्रीट एक्सपीरियंस कैनोपी के नीचे लगभग एक जैसा मोनोलिथ दिखाई दिया था। मोनोलिथ रहस्यों का सिलसिला यूटा में शुरू हुआ जब रेगिस्तान में रहस्यमयी खंभे देखे गए और 2020 में कैलिफोर्निया में भी। स्थानीय लोगों ने सैन लुइस ओबिस्पो काउंटी में एटास्केडरो, कैलिफोर्निया में पाइन माउंटेन के शीर्ष पर एक और मोनोलिथ देखा था।

दो हफ्ते पहले, वन्यजीव अधिकारियों को रेड रॉक डेजर्ट, यूटा में एक ऐसी ही अजीब संरचना मिली थी - हालांकि इसे तब से हटा दिया गया है। कुछ ही समय बाद, रोमानियाई पहाड़ी पर पाया गया एक समान मोनोलिथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। स्काई न्यूज के अनुसार, 'द मोस्ट फेमस आर्टिस्ट' नामक एक अनाम समूह ने यूटा और कैलिफोर्निया में मोनोलिथ का श्रेय लिया है।

मोनोलिथ क्या है?

हाल के वर्षों में दुनिया भर में मोनोलिथ एक रहस्यमयी घटना के रूप में दिखाई दे रहे हैं। एक मोनोलिथ तकनीकी रूप से पत्थर का एक एकल खंड है, जिसे आमतौर पर एक स्तंभ के आकार में बनाया जाता है। भूगोल विशेषज्ञों ने रेगिस्तान में पाई गई एक अजीब, 12 फ़ीट ऊंची वस्तु को मोनोलिथ बताने के लिए यूटा सरकार के अधिकारियों की खिंचाई की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा लगता है कि इसे पत्थर से नहीं बल्कि धातु से बनाया गया है। हालांकि, द गार्जियन बताता है कि मेरियम वेबस्टर की डिक्शनरी मोनोलिथ की 'एक विशाल संरचना' के रूप में व्याख्या करती है। साथ ही, मोनोलिथ वह शब्द है जिसका इस्तेमाल निर्देशक स्टेनली कुब्रिक द्वारा 2001: ए स्पेस ओडिसी में प्रसिद्ध की गई संरचना का वर्णन करने के लिए किया गया है।

भारत में लॉन्च हुई नई बीएमडब्ल्यू आर 1300 जीएस

अभी तक का सबसे शक्तिशाली बीएमडब्ल्यू बॉक्सर इंजन

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

नई बीएमडब्ल्यू आर 1300 जीएस को भारत में लॉन्च किया गया है। बीएमडब्ल्यू मोटोराड इंडिया ने भारत में नई बीएमडब्ल्यू आर 1300 जीएस लॉन्च किया है। यह ऐडवेन्चर मोटरसाइकिल कम्प्लीटली बिल्ट-अप यूनिट (CBU) के रूप में मिलेगी और जून 2024 से इसकी डिलिवरी आरंभ होगी। श्री विक्रम पावाह, प्रेसिडेंट, बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने कहा कि, 'बीएमडब्ल्यू मोटोराड ने चार दशक से भी ज्यादा पहले आर 80 जी/एस के साथ टुअरिंग एंड्यूरोज का नया सेगमेंट स्थापित किया था। और तब से लेकर बॉक्सर इंजन वाली बीएमडब्ल्यू जीएस प्रतिस्पर्धी फील्ड का निर्विवाद लीडर रही है। नई बीएमडब्ल्यू आर 1300 जीएस के साथ बीएमडब्ल्यू मोटोराड ने जीएस को और भी तेज बनाने पर फोकस किया है। यह शक्ति, आराम और फुर्ती का खूबसूरत संयोजन है, जो इसे किसी भी भू-भाग के लिए आदर्श मोटरसाइकिल बनाता है। अपनी विलक्षणता और आकर्षण के साथ ऑल-न्यू बीएमडब्ल्यू आर 1300 जीएस सर्वोच्च अपेक्षाओं से भी आगे निकलेगी। आपको कुछ भी रोक नहीं सकता, विशेषकर ऑन-रोड होने पर!' ग्राहकों को अपनी पसंद की बीएमडब्ल्यू मोटोराड मोटरसाइकिल खरीदने में सक्षम बनाने के लिए बीएमडब्ल्यू फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया कस्टमाइज्ड और लचीले फाइनेंशियल सॉलूशंस प्रदान करेगी। ग्राहक डिलिवरी होने के पहले भी अपने लोन्स स्वीकृत करा सकते हैं। मन की पूरी शांति के लिए सभी बीएमडब्ल्यू मोटोराड बाइक्स 'तीन साल और असीमित किलोमीटर्स' के लिए स्टैण्डर्ड वारंटी के साथ आती हैं, जिसमें वारंटी को चौथे और पांचवें वर्ष तक विस्तारित करने का विकल्प उपलब्ध है। साथ ही रोड-साइड असिस्टेन्स, जो एक 24x7 365 दिन पैकेज है, ब्रेकडाउन और टोईंग की स्थितियों में त्वरित सेवायें सुनिश्चित करता है।

'जब तक खाने-पीने की चीजें सस्ती नहीं होती महंगाई से लड़ाई रहेगी जारी'

RBI बुलेटिन में टिप्पणी

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 19 जून के नवीनतम मासिक बुलेटिन में दावा किया है कि मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत के लक्ष्य पर लाने की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक खाद्य पदार्थों की कीमतों पर दबाव बना रहेगा। आरबीआई के 'मासिक अर्थव्यवस्था की स्थिति' लेख में कहा गया है, 'जब तक खाद्य कीमतों का दबाव बना रहता है, तब तक मुद्रास्फीति को उसके लक्ष्य (4%) पर लाने की कोशिशें जारी रहेंगी।' केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4 प्रतिशत निर्धारित किया है, जिसमें दोनों तरफ 2 प्रतिशत की छूट है।

डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा जो मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) में तीन आरबीआई प्रतिनिधियों में से एक हैं, लेख के सह-लेखकों में से एक हैं। आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा, लेख में व्यक्त विचार केंद्रीय बैंक के आधिकारिक रुख को नहीं दर्शाते हैं।

प्रचंड गर्मी से सब्जियों और फलों का उत्पादन प्रभावित होने की आशंका: आरबीआई

केंद्रीय बैंक के जून बुलेटिन के अनुसार असाधारण गर्मी और जलाशयों के घटते स्तर से सब्जियों और फलों का उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। यह स्थिति नीति निर्माताओं के लिए नई परेशानी पैदा कर सकता है। आरबीआई की जून बुलेटिन के अनुसार गंभीर हीटवेव महंगाई को कम करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में बाधा पैदा कर रहा है। आरबीआई बुलेटिन में कहा गया है कि केंद्रीय बैंक खुदरा मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत के लक्ष्य पर लाने की कोशिश कर रहा है, पर यह प्रक्रिया अस्थिर और उच्च खाद्य कीमतों से बाधित हो रही है।

आरबीआई गवर्नर ने कहा- रबी फसलों के आवक की निगरानी की आवश्यकता

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने केंद्रीय बैंक के बुलेटिन के जून संस्करण में कहा, 'असाधारण गर्मी और जलाशयों का घटा हुआ स्तर सब्जियों और फलों उत्पादन पर दबाव डाल सकते हैं। दालों और सब्जियों की रबी आवक की भी सावधानीपूर्वक निगरानी करने की आवश्यकता है।' दास ने कहा कि भारत में खुदरा मुद्रास्फीति मार्च-अप्रैल की अवधि में नरम हुई, लेकिन खाद्य पदार्थों की उच्च कीमतों कारण अपेक्षित राहत नहीं मिली। देश के कई हिस्से वर्तमान में प्रचंड गर्मी की चपेट में हैं। खासकर उत्तर भारत को हीटवेव ने अपनी चपेट में ले रखा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति लंबे समय तक बनी रह सकती है, हालांकि जल्द ही मानसून से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

चीन और बांग्लादेश को भा गई भारत की मिर्ची

रेकॉर्ड पर पहुंच गया भारत से मसालों का एक्सपोर्ट

नई दिल्ली। एजेंसी

हॉन्ग कॉन्ग और सिंगापुर ने कुछ भारतीय कंपनियों के मसालों पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही कई अन्य देशों ने भारतीय मसालों को निगरानी लिस्ट में डाला है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत से मसालों का एक्सपोर्ट रेकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। इस दौरान भारत से मसालों का एक्सपोर्ट 4.46 अरब डॉलर रहा जो पिछले साल के मुकाबले 17 फीसदी अधिक है। वॉल्यूम के लिहाज से भी यह नौ फीसदी की तेजी के साथ 15.39 लाख टन रहा। इस दौरान खासकर काली मिर्च, इलायची और हल्दी महंगे होने के कारण भारत को अच्छी कमाई हुई।

मार्जिन बनाए रखने के लिए FMCG कंपनियों ने बढ़ाईं कीमतें, बढ़ा घरेलू खर्चा

नई दिल्ली। एजेंसी

फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (इफ्ण्ड) कंपनियों द्वारा पिछले 2-3 महीनों में कुछ खाद्य पदार्थों और पर्सनल केयर ब्रांडों के उत्पादों और श्रेणियों पर 2 से 17 प्रतिशत तक की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस कारण घर चलाने का खर्चा बढ़ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनियों ने साबुन और बॉडी वॉश पर 2 फीसदी से 9 फीसदी, बालों के तेल पर 8 से 11 फीसदी और चुनिंदा खाद्य पदार्थों पर 3 से 17 फीसदी तक कीमतें बढ़ाई हैं।

एक साल तक कीमतों में गिरावट के बाद अब बढ़ने लगे दाम

यह वृद्धि लगभग एक साल तक कीमतों में गिरावट के बाद हुई है, जिसका श्रेय कमोडिटी की कीमतों में नरमी को दिया जा सकता है। उच्च इनपुट लागत के कारण मार्जिन बनाए रखने के लिए 2022 और 2023 की शुरुआत में कीमतें बढ़ाने के बाद, FMCG कंपनियों ने वित्त वर्ष 2024 के अधिकांश समय में कीमतों में बढ़ोतरी से परहेज किया, लेकिन अब कीमतें फिर से बढ़ना शुरू हो गई हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कच्चे तेल और पाम तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद, दूध, चीनी, कॉफी, खोपरा और जौ जैसी अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। बीकाजी (Bikaji) का इरादा वित्त वर्ष 2025 में कीमतें 2-4 प्रतिशत बढ़ाने का है, यह प्रक्रिया अप्रैल में ही शुरू हो चुकी है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने भी अपने

प्रतिस्पर्धियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए मूल्य समायोजन (price adjustments) पर काम करना शुरू कर दिया है। डाबर इंडिया और इमामी ने संकेत दिया है कि वे इस साल लो सिंगल डिजिट में कीमतों में वृद्धि करेंगे।

साबुन से लेकर कॉफी तक 2 से लेकर 17 फीसदी तक की वृद्धि

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज एंड ट्रेड के आंकड़ों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने साबुन की चुनिंदा स्टॉक-कीपिंग यूनिट्स पर कीमतों में 4-5 फीसदी की बढ़ोतरी की है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने डव की कीमतें 2 फीसदी बढ़ा दी हैं, जबकि विप्रो ने संतूर की कीमत 3 फीसदी बढ़ा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैंबल हाइजीन एंड हेल्थ केयर और ज्योति लैब्स के डिटर्जेंट ब्रांडों ने चुनिंदा पैक्स पर कीमतों में 1-10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने पोर्टफोलियो में शैम्पू की कीमतों में कम से मिड सिंगल डिजिट प्रतिशत और स्किन केयर उत्पादों में 4 प्रतिशत तक की वृद्धि की है। महंगाई के दबाव के कारण नेस्ले ने कॉफी की कीमतें 8-13 प्रतिशत बढ़ा दी हैं।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।